

189

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1
संख्या- /XVI-1/13/10(27)/2012
देहरादून: दिनांक: 11 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उत्तराखण्ड सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं राजसहायता देने का अधिकार दिया गया है। इस कार्यक्रम के सुचारु संचालन एवं इस मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का विवरण, लागत, राज सहायता एवं विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/ उच्चीकरण:- परियोजना लागत में से तकनीकी सिविल कार्य एवं प्लान्ट एवं मशीनरी का एक तिहाई अधिकतम अनुदान रु0 75.00 लाख प्रति परियोजना अनुमन्य है।

- इस योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख तक की राज सहायता के प्रकरण मिशन, निदेशक, एनएमएफपी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा रु0 25.00 लाख से रु0 75.00 लाख तक की राज सहायता के प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

2. शीत श्रृंखला सुविधा का नॉन हार्टिकल्चर उत्पाद एवं रिफर व्हीकल की स्थापना:- इस योजना पर प्रति परियोजना राज सहायता 75 प्रतिशत परियोजना लागत में से सिविल कार्य एवं मशीनरी का अधिकतम रु0 10.00 करोड़ तक प्रति परियोजना अनुदान देय है।

- इस योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख रुपये तक की राज सहायता के प्रकरण मिशन, निदेशक, एनएमएफपी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा रु0 25.00 लाख से रु0 1.00 करोड़ तक की राज सहायता के प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे एवं रु0 1.00 करोड़ के अधिक के प्रकरण मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

3. मानव संसाधन विकास योजना:- इस योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ हैं:-

3.1 खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अधिकतम रु0 75.00 लाख अनुदान देय है।

- इस योजना की राज सहायता के प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

3.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0):- इस योजना के तहत प्रति ई0डी0पी0 रु0 2.00 लाख राज सहायता देय है।

- इस योजना की राज सहायता के प्रकरण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

3.3 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एफ0पी0टी0सी0):- इस योजना के तहत एकल उत्पाद रु0 6.00 लाख तथा बहुउत्पाद हेतु रु0 15.00 लाख अनुदान प्रति परियोजना देय है।

- इस योजना की राज सहायता के प्रकरण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

4. सेमिनार/कार्यशाला आदि का आयोजन:- इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 3.00 लाख प्रति कार्यक्रम अनुदान देय है।

- इस योजना की राज सहायता के प्रकरण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

5. अध्ययन/सर्वे आदि कराया जाना:- इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 3.00 लाख प्रति कार्यक्रम अनुदान देय है।

- इस योजना की राज सहायता के प्रकरण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के स्तर पर स्वीकृत किये जायेंगे।

6. मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में Preparatory activities (प्रारम्भिक कार्यक्रमों) (जैसे विजन डायक्व्यूमेन्ट तैयार करना, योजना का प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यय) हेतु रु0 एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र (1.125 करोड़) की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। आगामी वर्ष से इन कार्यक्रमों के लिये मिशन मैनेजमेन्ट मद में पृथक से वार्षिक कार्य योजना की कुल धनराशि का 03 से 05 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत योजना के संचालन हेतु रखे गये सलाहकार एवं संविदा/प्रतिनियुक्ति/आउट सोर्सिंग के आधार पर रखे जाने वाले कार्मिकों के मानदेय/व्यवसायिक शुल्क/टी0ए0 एवं डी0ए0 आदि का भुगतान, उक्तवत पदों को भरे जाने हेतु एवं योजना के प्रचार-प्रसार तथा कार्यालय के विभिन्न प्रकार के अनावर्तक/आवर्तक व्ययों/वाहन व्यवस्था एवं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत व्यय करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

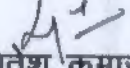
अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 126/XVI-1/13/10(27)/2012, तददिनांकित:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, देहरादून।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।
3. मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून।
- ✓ 4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को उक्त कार्यालय ज्ञाप को जनसाधारण के सूचनार्थ शासकीय वेबसाइट में प्रदर्शित कराने हेतु।
5. उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, /उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 फलोद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, अपर सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।